

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राज-पत्र</b> विशेषांक	Regd. No. RJ. 2777/93 <b>RAJASTHAN GAZETTE</b> Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 16, गुरुवार, शके 1917—अप्रैल 6, 1995 Chaitra 16, Thursday, Saka 1917—April 6, 1995	

भाग 4 (क)  
राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम ।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(Group-II)

### NOTIFICATION

Jaipur, April 6, 1995

No. F. 2(25) Vidhai/2/90.—The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the President on the 24th day of March, 1995 and is hereby published for general information:—

**THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1990**

(Act No. 5 of 1995)

[Received the assent of the President on the 24th day of March, 1995]

An

Act

further to amend the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Forty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title and commencement.*—(1) This Act may be called the Rajasthan Urban Improvement (Amendment and Validation) Act, 1990.  
(2) It shall come into force at once.

2. *Substitution of section 60-A, Rajasthan Act 35 of 1959.*—The existing section 60-A of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959

*mechi*

(Rajasthan Act 35 of 1959) shall be deemed to have been substituted on the 1st day of August, 1987 by the following, namely:—

- 60-A. *Transitory provisions for pending matters relating to acquisition of land.*—(1) Notwithstanding anything otherwise contained in sub-section (1) of section 52, where, in any matter relating to the acquisition of land pending between 24th day of September, 1984 and 31st July, 1987, an action, thing or order has been taken, done or made under and in accordance with the provisions of this Act, as it stood before the 1st day of August, 1987, such action, thing or order shall not be re-opened or reviewed or be liable to be challenged on the ground that such action, thing or order was at variance with that provided in the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894) (here in- after in this section referred to as the Land Acquisition Act) subject, however, that any further proceeding, action or order in such matter conducted, taken or made on or after the 1st day of August, 1987 shall, subject to the other provisions of this section, be made under and in accordance with the Land Acquisition Act.
- (2) The amount of compensation or interest or that payable for any other reason shall, in a matter pending on the 1st day of August, 1987, be payable under and in accordance with the provisions of the Land Acquisition Act and the money paid prior to the 1st day of August, 1987 shall be deducted from or adjusted against the said amount.
- (3) Where in a matter pending on the 1st day of August, 1987, a notice under sub-section (2) of section 52 or a notice under sub-section (1) thereof has been served or, as the case may be, published, such notice shall be deemed to be the notification or declaration published or made under sub-section (1) of section 4 or, as the case may be, under sub-section (1) of section 6 of the Land Acquisition Act and the declaration or award in such a matter shall be made within a period of one year or, as the case may be, two years from the 1st day of August, 1987.

- (4) Where any land has, prior to the 1st day of August, 1987, vested in the State Government or its possession has been taken in accordance with the provisions of this Act as it stood before the 1st day of August, 1987, such vesting or possession of land shall not be liable to be challenged on the ground that no amount of compensation was tendered and paid in accordance with sub-section (3-A) of section 17 of the Land Acquisition Act, subject, however, that such amount shall be tendered and paid within a period of six months from the 1st day of August, 1987.
- (5) In determining the amount of compensation to be awarded in a matter pending on the 1st day of August, 1987, the market value of the land at the date on which the notice was published in the Official Gazette under sub-section (2) of section 52, as it stood before the 1st day of August, 1987, shall be taken into consideration.
- (6) An appeal filed under section 54 or section 56 or a dispute referred to under section 55 or section 59 and pending on the 1st day of August, 1987 shall be decided having regard to the provisions of the Land Acquisition Act."

3. *Validation.*—Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order or finding of any court, tribunal or Authority to the contrary, any action, thing or order taken, done or made under and in accordance with the provisions relating to acquisition of land contained in the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), shall be deemed to be valid and effective as if such action, thing or order has been made, taken or done under the said Act as amended by this Act.

जे. पी. बंसल,  
Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 6, 1995

संख्या प. 2 (25) विधायी/90.-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दो अरबन इम्प्रूवमेन्ट (अमेन्समेन्ट एण्ड बेनीडेशन) एक्ट, 1990 (एक्ट नम्बर 5 ऑफ 1995)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनाार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

(हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम,

1990

(1995 का अधिनियम संख्या 5)

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 1995 को प्राप्त हुई] :-

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 को और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्न लिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगर सुधार (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1990 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. 1959 के राजस्थान अधिनियम 35 की धारा 60-क का प्रतिस्थापन. - राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 35) की विद्यमान धारा 60-क के स्थान पर, 1 अगस्त, 1987 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात् :-

"60क-भूमि के अर्जन से संबंधित लम्बित मामलों के लिए अन्तःकालीन उपबंध. -

(1) धारा 52 की उप-धारा (1) में अथवा अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां 24 सितम्बर, 1984 और 31 जुलाई, 1987 के बीच में लम्बित भूमि के अर्जन से संबंधित किसी भी मामले में, इस अधिनियम के, जैसा कि यह 1 अगस्त, 1987 के पूर्व था, उपबंधों के अधीन और अनुसार कोई कार्रवाई, बात या आदेश किया गया हो वहां ऐसी कार्रवाई, बात या आदेश को इस आधार पर पुनः नहीं खोला जायेगा, न पुनर्विलोकित किया जायेगा और न वह आशेषित किये जाने के दायित्वधीन होगा कि ऐसी कार्रवाई, बात या आदेश उससे भिन्न था

(5) 1 अप्रैल, 1987 को बंजारा किसानों की मांगों में प्रतिनिधित्व करने वाले मुखियाओं की एक समिति बनाने के लिए, भारत सरकार ने 52 की उप-धारा (2), भारत अधिनियम 1987 के धारा 1, के अंतर्गत राज-पत्र में विषय सूची के तहत अधिनियम बनाने की शक्ति प्रदान की जायेगी।

(4) जहाँ कोई भी भूमि 1 अगस्त, 1987 के पूर्व राज्य सरकार में निहित हो गई है या उसका कब्जा इस अधिनियम के, जहाँ कि यह 1 अगस्त, 1987 के पूर्व था, उपबन्धों के अन्वय में लिया गया है, वहाँ भूमि का ऐसा निहित होना या कब्जा लिया जाएगा इस आधार पर अधिनियम के अन्वय में नहीं होगा कि मुआवजे की रकम भूमि अर्जन किया जाने के परिपक्वता पर नहीं होगी कि मुआवजे की रकम भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के अन्वय में निहित होकर खर्च नहीं की गई थी, तथापि, ऐसी रकम 1 अगस्त, 1987 से छः मास

(3) जहाँ 1 अगस्त, 1987 को विधान सभा में धारा 52 की उप-धारा (2) के मा उपरकी उप-धारा (1) के अन्तर्गत नॉटिस लाना था, धारिणी प्रकाशन किया गया है, वहाँ ऐसा नॉटिस पूर्व अर्द्ध प्रकाशन की धारा 4 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत था, धारिणी, धारा 6 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत की गयी प्रकाशन या की गयी घोषणा समझी जायेगी और ऐसे किसी मामले में घोषणा या धारा 1 अगस्त, 1987 से एक वर्ष या, या निर्दिष्ट, दो वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर किया जायेगा।

(2) मुआवजे पर दायज की रकम प्रथम बड़े रकम, जो किसी भी अन्य कारण से संदेह हो, 1 अप्रैल, 1987 को जमावत किया जाएगा। यदि, यदि मुआवजे प्रतिनिधियों के अवांछित और अनुपार संदेह होना और 1 अप्रैल, 1987 के पूर्व संदेह पर अवलोकन रकम से से करा जायेगा। पर उसके प्रति समाप्त किया जायेगा।

[illegible]

-----

जे. पी. बंसल,  
शासन सचिव ।

किया गया है ।  
कारिवाई, बाद में आदेश इस अधिनियम द्वारा म्या-संश्लेषित उक्त अधिनियम के अधीन  
करवाई, बाद में आदेश इस प्रकार अधिनियम और म्यादी समझौता जमाया गया है  
अनुविवेक, म्या के अधीन से संबंधित उपबंधों के अधीन और अधिनियम की म्या की गई म्या  
मी, राजस्थान म्या म्या अधिनियम, 1959 ( 1959 का राजस्थान अधिनियम 35 ) से  
मी म्या, इसी में आदेश में अनुविवेक किया बाद के प्रतिकूल होने पर  
3. अधिनियमकरण.—किसी म्या म्या, अधिनियम, अधिनियम या अधिनियम के किसी  
उपबंधों की म्या से रखते हुए विनिर्दिष्ट किया जाएगा । ” ।  
विवाद, जो 1 म्या, 1987 को निवृत्त है, म्या म्या अधिनियम के